

"मुझे अखबार निकालने दो तो मैं इस बात की परवाह नहीं करता कि कौन धर्म का नियामक है और कौन कानून का निर्माता"—वेडेल फिलिप्पा

दैनिक भारतीय बस्ती

बस्ती 9 जनवरी 2024 मंगलवार

सम्पादकीय

सूरज की खोज में इसरो

भारतीय अंतरिक्ष वैज्ञानिक हाल के दिनों में आसमानी सफलता की नयी इबारत लिख रहे हैं। पिछले वर्ष अगस्त में चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर चंद्रयान-3 की सफल लैंडिंग के एक सप्ताह के भीतर ही भारत ने सूरज विषयक नया ज्ञान जुटाने के लिये आदित्य एल-1 मिशन शुरु किया था। हर भारतीय के लिये गर्व की बात है कि पृथ्वी से लगभग पंद्रह लाख किमी दूर आदित्य अपने लक्ष्य तक सफलतापूर्वक पहुंच गया है। जो बताता है कि कैसे इसरो के वैज्ञानिक बेहद जटिल व मुश्किलों से भरे अभियानों को सहजता से तार्किक परिणति दे रहे हैं। भारतीय वैज्ञानिकों की बड़ी उपलब्धि यह भी है कि तमाम सफलताएं इतनी कम लागत में हासिल की गई हैं कि पूरी दुनिया दांतों तले उंगली दबा लेती है। इस तरह भारत विज्ञान की उन सीमाओं को विस्तार दे रहा है जो कालांतर शेष दुनिया के लिये कल्याणकारी साबित होंगी। शुरुआती संकेत बता रहे हैं कि मिशन के सभी अवयव सुचारु रूप से अपना काम कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि आदित्य अगले पांच वर्षों तक शोध व अनुसंधान के कार्यों के जरिये मानवता के कल्याण के लिये नई जानकारी जुटाएगा। इस मिशन की सफलता ने उन संभावनाओं को भी गति दी है, जो भविष्य में अन्य ग्रहों में शोध-अनुसंधान के लिये मार्ग प्रशस्त कर सकती हैं। इस तरह पहले सूर्य मिशन में भारत ने अंतरिक्ष में सूर्य की निगरानी करने वाली ऑर्बिटर स्थापित कर दी है।

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन साल 2023 में इतिहास रचने के बाद नए साल से नए जोश और मिशन के साथ आगे बढ़ रहा है। 2024 में इसरो एक बार फिर इतिहास रचने जा रहा है। इस बार इसरो ने अंतरिक्ष में इतिहास रचने के लिए अंतरिक्ष की नंबर वन कंपनी स्पेस एक्स से हाथ मिलाया है। इसरो साल 2024 की तिमाही में अपने संचार सैटेलाइट जीएसएटी-20 को अंतरिक्ष कंपनी स्पेस-एक्स की मदद से लॉन्च करने वाला है। ऐसा पहली बार हो रहा है जब इसरो अपने किसी मिशन को लॉन्च करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेस एक्स के फाकन-9 हेवी लिफ्ट लॉन्चर का प्रयोग करेगा। स्पेस एक्स उद्योगपति एलन मस्क की कंपनी है, जिसकी 2002 में स्थापना की गई थी।

दरअसल, लैंग्वेज पाइंट तक पहुंचा आदित्य एल-1 धरती के इस करीबी ग्रह में होने वाली विभिन्न प्रक्रियाओं का अध्ययन, अंतरिक्ष के मौसम व सौर प्रवाह के धरती पर पड़ने वाले प्रभावों के विश्लेषण का मार्ग प्रशस्त करेगा। बीते साल दो सितंबर को प्रक्षेपित किए गए सूर्य मिशन का लक्षित कक्षा में सफलतापूर्वक पहुंचना हमारे वैज्ञानिकों की मेधा व सटीक योजना का ही परिणाम है। उल्लेखनीय है कि जिस बिंदु पर आदित्य को पहुंचाया गया है वहां सूरज व धरती का गुरुत्वाकर्षण बल संतुलित होता है, जिसके चलते अंतरिक्ष यान को कम ईंधन की जरूरत होती है। वह कम ईंधन में अधिक समय तक वैज्ञानिक शोध-अनुसंधान कर सकता है। दरअसल, आदित्य यान में मौजूद सात पेलोड्स सूर्य की बाहरी परत, ऊर्जा और अंतरिक्ष में होने वाली अन्य गतिविधियों का अध्ययन करेंगे। साथ ही उन कारकों की पड़ताल को धरती व अंतरिक्ष के मौसम को प्रभावित करते हैं। दरअसल, सौर प्रवाह के चलते धरती पर कई तरह की वैज्ञानिक घटनाएं सामने आती हैं। अब वैज्ञानिक सूर्य के विकिरण तथा धरती पर उसके प्रभावों के बारे में भी अधिक जानकारी जुटा पाएंगे। निश्चित रूप से आदित्य मिशन की सफलता से भारतीय वैज्ञानिकों के सूर्य को लेकर ज्ञान में वृद्धि होगी। जो कालांतर मानवता के कल्याण और अंतरिक्ष से आसन्न खतरों से बचाव का मार्ग दिखाने में सहायक होगा। विश्वास किया जाना चाहिए कि साढ़े चार करोड़ डॉलर बजट वाले इस आदित्य मिशन से भविष्य में देश को भरपूर लाभ मिल सकेगा। इसरो जिस तेजी से अपने मिशन में आगे बढ़ रहा है यह भारत के लिये बड़ी उपलब्धि है।

यादों की कसक में श्रीराम मंदिर



राजेश रामचंद्रन

जनवरी की एक बकीली सुबह को पड़ोस की श्रमिक कालोनी से आते ऊंचे नारों से नींद टूटी। नारे थे जय श्री राम के और एक छोटा झुंड पर-पर जाकर अयोध्या में 22 जनवरी को राम मंदिर में राम लला की मूर्ति के प्राण-प्रतिष्ठा समारोह के बारे में सूचना दे रहा था। मैंने खुद को अन-आमंत्रित महसूस किया। क्या यह इसलिए कि मुझको भी वे मैकालेयुन मानकर या सटीकता से कहें तो बर्चिलेयुन की तरह ले रहें हैं, जिसे किसी भी भारतीय चीज या हिंदू शब्द से बिड़ थी या फिर मैं उनके आक्रामक हिंदू राष्ट्रवाद का साथ न देने वाला एक गांधीवादी अमनपसंद व्यक्ति हूँ।

रैं, मैकालेयुन, गांधीवादी राष्ट्रवादी और हिंदू पुनर्जागरण कर्तृद्वय सत्य या प्रायः गाली जैसी शब्दावली में वे तीनों मौजूद भारतीय भारत की मुख्य राजनीतिक मानना बना रहा और यह जातीय, क्षेत्रीय और भाषाई भेदों पर भारी पड़ता है। हिंदू पुनरुत्थानवादियों की जीत के पीछे खुरद को भारतीय राष्ट्रवाद का एकमात्र बज्रवाहक होने की दावेदारी



की सफलता है, जिसे उन्होंने आसानी से धार्मिक-राजनीतिक परिप्रेयोजना में तब्दीक कर डाला और यहां पर राजनीतिक चलन की अन्य दो धाराएं परत हो गईं।

पहली हार हुई गांधीवादी राष्ट्रवादियों की। जब तक इसका जोर रहा, हिंदू दक्षिणपंथी पुनरुत्थानवादी मुख्यधारा का राजनीतिक दल नहीं बन पाए। वास्तव में जब भारतीय जनता पार्टी का गठन हुआ तो इसने गांधीवादी समाजवाद को अपना मार्गदर्शक सिद्धांत बताया था, जो भारतीय राष्ट्रवाद के इस शायदश प्रतीक को नुनाने का प्रयास था। इसी बीच कांग्रेस में गांधीवादी राष्ट्रवाद के उत्तराधिकारियों ने इस विचार को हिंदू-मुस्लिम एकाता और सौहार्द में तब्दीक करते हुए प्रगतिशील इस्लामिक मीलानाओं का तुष्टिकरण करके, जिन्हें धार्मिक आधार पर अलगाववाद तक से गुरेज नहीं था, अपने नए सिद्धांतों का मझौल बना डाला।

सलमान रश्दी की किताब सेटैनिट वॉर्स पर प्रतिबंध, शाह

बानो मामले में अदालती फैसले को उलटाना और जिल्ना की मुस्लिम लीग से पुराना गठबन्धन कायम रखने वाले दोहरे चरित्र ने साम्प्रदायिक आधार पर राजनीति करके वाले सत्ता हथियाने के आरोपों को कैसा दे डाली। यदि इस्लाम का इस्तेमाल वोट पाने के लिए हो सकता है तो फिर हिंदुत्व क्यों नहीं? दबतर भूमिका रही नव-भारत के वामपंथी छद्म-बुद्धिजीवियों की, जिन्होंने पूर्व-आधुनिक युगीन इस्लामिक प्रतिगामिता को न्यायविरुद्ध सिद्ध करने में सारा जोर दिया। भारतीय वामपंथ, जो खुद को उत्तर-आधुनिक युगीन लोकतंत्र की आवाज होने का दावा करता है, वह इस्लामिक धार्मिक अलगाववादियों और कश्मीर से हिंदुओं के धार्मिक आधार पर सफाए को न्यायविरुद्ध बताने का हर संभव प्रयास करता रहा।

खे-बादू का सिद्धांत मैकाले की छोड़ न होकर चर्चिल की समक अविव था। तत्पश्चात्, उत्तर-आधुनिक युगीन शिक्षाविद, लेखक और राजनेता खुद को ऐसा समूह बताते रहे जिसे

ऐसे भारत की हिकल्यता स्वीकार्य नहीं, जिसमें परिदृष्टि और मुस्लिम एक साथ रहें। जब पश्चिमी साम्राज्य पुरस्कृत विजेता और पश्चिम-अनुमोदित शिक्षाविद साम्प्रदायिक अलगाववाद के शिकार बने लोगों की दयनीयता को नजरअंदाज करने लगे या धार्मिक आधार पर देश के टुकड़े करने की बात करने वालों की बैठकों में भाग लेने लगे, और जब औपनिवेशिक शासकों की तरह उनका हिंदू-राष्ट्रीय एजेंडा और प्रत्यक्ष होने लगा, तब उन्हें मैकालेयुन कहकर पुकारा जाने लगा।

आगे, इस प्रक्रिया में, भारतीय वामपंथ ने राष्ट्रवाद को अंधाधुनिक दुकान ठहराकर आलोचना करनी शुरू कर दी। इसमें मजबूत म् यमांगी दल (कांग्रेस) का तोड़ करने के बेशर्मी से जातीयता और भाषाई आधार पर अलगाववाद को हथियार बनाया। इंदिरा गांधी जैसा नेता, जो पश्चिम-प्राधान्यता को चुनौती देने की कूत रखता हो, कहीं ऐसा कोई और नेता न उभर आए, यह उर नव

भारतीय वामपंथ में तारी रहा, जिसमें ज्यादातर गिनती पश्चिमी शिक्षाप्राप्त या पश्चिमी सोच से ओतप्रोत शिक्षाविदों, लेखकों और पत्रकारों की है। एक राष्ट्रीय पत्रिका के पहले संस्करण में दावा किया गया कि 70 फीसदी कश्मीरी भारत से अलग होना चाहते हैं, हालांकि किस सर्व को आर बनाया यह आज तक रहस्य है। यह 1990 के दशक की उथल-पुथल थी, जब दक्षिणपंथी हिंदुत्व इस नव-वामपंथ और पुरानी कांग्रेस के गांधीवादी राष्ट्रवाद के वारिस झंडाबंदारों से मुकाबले को बतौर एक मान्य ताकत बनकर उभरने लगा।

आज भी, राहुल गांधी मानते हैं कि जातिगत गुणना हिंदू राष्ट्रवाद पर भारी पड़ेगी, क्या उन्हें अहसास है कि जिस अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए वे लगभग 40 प्रतिशत आरक्षण चाहते हैं, पहले स्वयं अपने संगठन में मुख्यमंत्री या पदाधिकारी चुनने से हिंदुत्व आर्वादन करने में लागू कर दिखाना चाहिए। दरअसल, शंशवादी कांग्रेसी नेताओं ने जुर्मल जागरूक जातीयता और धार्मिक पहचान आधारित रसा हिंदू स्वस्वरु बनाया चाह है जिसके लिए भगवान राम एक इशक और आभासी चरित्र हो। इसका तोड़ करने को, नव वामपंथियों ने मध्ययुगीन इतिहास को खगाते लगे, यह सिद्ध करने की कोशिश की कि बाबर सीक था, यह मुसलमान हुए कि बाजपा टीक थी। बाहेगी ताकि राष्ट्रवाद को बतौर एक राजनीतिक मंच हड़प सके।

हिंदू आंदोलन उस आक्रमणकारी के हिंदुओं के संकेत पवित्र नगर में मरिडान बनवाने को सही कैसे मान लें? ऐसा कोई भी हिंदू परिवार न होगा जिसमें राम की पूजा न हो या रामायण पाठ या आराधना या रीतियों का पालन न हो। पश्चिमी सोच में रंगे बुद्धिजीवियों के हिंदू

जनमानस के विरुद्ध मचाए शोर ने लोगों को उनसे विमुख किया, जिसे आरएसएस के एजेंडे ने स्वरूप देकर, राम मंदिर को हिंदू पुनरुत्थान सम्राज्य का प्रतीक बना डाला। साल 1977 में, भारतीय राजनीति में जब स्वतंत्रता पार्टी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस (संगठन), लोक दल और समाजवादी दल ने मिलकर इंदिरा गांधी से मुकाबला करने को जनता पार्टी बनायी तो बतौर एक घटक जनसंघ की हैसियत एक छोटे खिलाड़ी की थी। यहां तक कि 1989 तक भी, बोफेर्स रिश्त प्रकरण पर खूब प्रचार करने के बावजूद बाजपा कांग्रेस और जनता दल से काफ़ी पीछे थी।

फिर भी यह कहना गलत होगा कि बाजपा के उदय का श्रेय विधुद रूप से राम मंदिर आंदोलन को जाता है, जिसकी वास्तविक परिणति 1992 में बाबरी मस्जिद विध्वंस में हुई और इस पर कार्यवाही जारी रही। मस्जिद गिरते ही, जल्द ही आबादी युग का अंतिम मोड़ युग का आरंभ हुआ, जब 2010 में कॉमनवेल्थ खेलों की पूर्व संरक्ष में दिल्ली में नव-निर्मित पुल के गिरने, तैयारियों में कोताही और भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर यह जागरूकता का सबब बना।

भारत को सदा एक ऐसे मजबूत नेता की चाहत रही है जो अंतर्राष्ट्रीय नवशे का पुनर्निर्माण कर सके, नए इलाके मिलाए और एक महाशक्ति का इस्तेमाल दूसरी के विरुद्ध करे। इसकी बजाय, मंदिर निर्माण हिंदू जनमानस के इस डर को जीतने का पर्याय बन गया है कि कहीं कौनों की भ्रममसाहाहत में दूसरे दर्जे का नागरिक बनकर न रह जाए। मंदिर का उद्घाटन, जहां मध्ययुगीन यानों पर जीत की तरह है वहीं हिमालयी आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध का सरल अहसास भी कराती है। एक तरह से हिंदू दुर्दशा का लक्षण।

शैक्षिक पाठ्यक्रम आधुनिक तकनीक से समृद्ध हो



—सुरेश सेठ—

हमने 2024 में कदम रख लिया है। यह कदम है नये ज्ञान का, इंटरनेट ताकत का, बोट जीपीटी का और कृत्रिम मेधा का। रोबोटिक्स युग शुरू हो गया। इस युग के आविर्भाव के लिए हमें पहले तो देश की वास्तविकता की पहचान करनी होगी। यह देश जहां पर पिछड़े हुए इलाकों हैं, पहाड़ों में बिखरी हुई जनसंख्या है और हमारा ग्रामीण समाज है जिन्हें शिक्षा के नाम पर पुरालापंथी अत्याचारों द्वारा पुराने सिलेबस की वही रियायती शिक्षा पुरसी जाती है। लेकिन दूसरी ओर यह देश हमें कोशल विकास योजना। इस बदले हुए युग में युवाओं को इस्कर्टी के नये युग के अनुरूप ढालना पड़ेगा। कृत्रिम मेधा आ गई, 3डी प्रिंटिंग आ गई, रोबोटिक्स आ गई और डीपफैक का कुमवलन आ गया। इस साल की अंतिम मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने अत्येधन, नयी सोच, शोश और नये अध्यवसाय की बात की है लेकिन उन्होंने फिर चाहिए अधिक विवेक।

नीति आयोग का कहना है कि देश की सकल घरेलू आय का कम से कम 6 प्रतिशत शिक्षा विकास पर खर्च किया जाना चाहिए। लेकिन इस समय तक भी शिक्षा विकास पर हम केवल 2.9 प्रतिशत ही खर्च कर रहे हैं। कहा गया है कि इस बार अर्थव्यवस्था 2023-24 में हमने शिक्षा विकास पर 1.12 लाख करोड़ रुपया खर्च किया है। लेकिन पीछे मुड़कर देखते हैं तो 2019-20 में भी हमने 9.4 हजार करोड़ रुपया खर्च कर दिया था। जरूरत है इस समय शिक्षाओं को नई डिजिटल शिक्षा के आधार पर प्रशिक्षित किया जाए। बाहें देश में 740 एकलव्य मॉडल रॉजिस्ट्रेशन स्कूल बनाने का फैसला किया गया है, जिसमें 38 हजार शिक्षकों को नियुक्ति मिलनी ताकि शुरू से ही ये शिक्षक जमीनी स्तर



सरकार ने अपनी ओर से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तो स्थापित कर दी है, जिससे देश के हर उम्र के लोगों को पढ़ने के लिए किताबें और दूसरी सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन इस डिजिटल लाइब्रेरी को भरने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के शोध प्रभागों, नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट को भी ज्ञान बांटने के डिजिटल युग में प्रवेश करने के लिये पर्याप्त तैयारी करनी पड़ेगी।

पर शिक्षा की गुणवत्ता को बदलें और बेहतर बनाएं। शिक्षक इंग्लैंड, अमेरिका और सिंगापुर में प्रशिक्षण के लिए भेजे जाएं। सिंगापुर शिक्षा के बहनेरी मॉडल के तौर पर जाना जाता है। इसीलिए पंजाब सरकार ने शिक्षकों के युग सिरपुर्न में भेजे हैं लेकिन समग्र शिक्षा अभियान में सर्वश्रेष्ठ पहले तो शिक्षकों का चयन करने के लिए उनकी सीमा रेखाओं को काट दिया जाए और उससे पहले शिक्षकों की कमी तो पूरी की जाए।

प्राथमिक स्तर से लेकर उच्च शिक्षा तक तमाम पढ़ खाली पड़े हैं। कच्चे और अर्धवर्षा अत्याचार काम चला रहे हैं। शिक्षा युग को बदलना है और उससे जाना आधारित अध्यवस्था बनानी है तो यह अर्थात् अध्यवस्थाओं की नींव पर नहीं बनेगी। देश में ग्रामीणों को डिजिटल साक्षर बनाने के लिए एकल अभियान शुरू किया गया है। इसके लिए एकल शिक्षा ऑन बोल बसें देश के 20 से अधिक राज्यों में गांव-गांव घूमकर लोगों को कंप्यूटर से परिचित कराया रही है।

नया युग है, इसमें बच्चे की नहीं बल्कि बड़े भी कंप्यूटर प्रशिक्षण हासिल करने के साथ-साथ डिजिट भी होना चाहते हैं। लेकिन क्या जो एकल शिक्षा ऑन बोल का अभियान शुरू हुआ है, वह कारी होगा? अनुमान है कि इस गाड़ी पर प्रति वर्ष 12 लाख रुपये खर्च होते हैं। इसमें 9 करोड़ रुपये हैं। एक बार 18 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। वाहन में सौर ऊर्जा से चलने वाले जेनरेटर की भी व्यवस्था है। यहां सर्व ईंधन तक का उपयोग करने के लिए समक योजना है। बाहे अभी यह योजना झांझड, बिहार, उत्तर प्रदेश से लेकर मंडिखल शिक्षा तक कृत्रिम मेधा का वह सहारा दिया जाए कि जिसके बारे में अभी इसके सिलेबस पर आधुनिक ज्ञान से पिछड़ रहे हैं। डिजिटल आधारित अध्यवस्था बनानी है तो उसे बनाने की दृष्टि से लेकर कारगुजारी, पुस्तकों और सिलेबस तक सब बदलना पड़ेगा।

लेखक साहित्यकार हैं।

को डिजिटल साक्षर करने का लक्ष्य है। दरअसल, 42 हजार से 42 लाख तक जाने की यात्रा सबके सहयोग से ही पूरी हो सकती है।

सरकार ने अपनी ओर से नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी तो स्थापित कर दी है, जिससे देश के हर उम्र के लोगों को पढ़ने के लिए किताबें और दूसरी सामग्री उपलब्ध हो सकेगी। लेकिन इस डिजिटल लाइब्रेरी को भरने के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकार के शोध प्रभागों, नेशनल बुक ट्रस्ट और चिल्ड्रन बुक ट्रस्ट को भी ज्ञान बांटने के डिजिटल युग में प्रवेश करने के लिये पर्याप्त तैयारी करनी पड़ेगी।

देश में प्रधानमंत्री की इस वर्ष 14,500 पी.एच. श्रीस्कर स्थापित करने की योजना है, जिस पर अगले पांच सालों में 27,360 करोड़ रुपये की लागत आएगी। इससे 20 लाख से अधिक लोगों को फायदा मिलेगा। लेकिन 5 साल के लिए अंतराल में जो प्रतीक्षा डिजिटल होत में लोगों को करनी पड़ेगी, उसके लिए अति आवश्यक है कि तत्काल इस दिशा में कदम बढ़ाने के लिए शिक्षा के वर्तमान मुद्दे में आमुल-बुल परिवर्तन हो। अर्थात् पालिटिकल से लेकर इंडीपेंडेंसी तक और आयुर्वेद से लेकर मेडिकल शिक्षा तक कृत्रिम मेधा का वह सहारा दिया जाए कि जिसके बारे में अभी इसके सिलेबस पर आधुनिक ज्ञान से पिछड़ रहे हैं। डिजिटल आधारित अध्यवस्था बनानी है तो उसे बनाने की दृष्टि से लेकर कारगुजारी, पुस्तकों और सिलेबस तक सब बदलना पड़ेगा।

लेखक साहित्यकार हैं।

मालदीव प्रकरण और भारत



—निरज कुमार दुबे—

भारत हमेशा 'पड़ोस प्रथम नीति' को आगे रखकर चलता है लेकिन पिछले पड़ोसी ही आंध्र दिखाने लगे तो उसे लगे हाथ तगड़ा जवाब भी दे दिया जाता है। कर्म में डूब चुके मालदीव को भारत ने लगातार आर्थिक मदद देकर उबार। वहां बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में अपना पैसा लगाया, भुखमरी और महामारी के समय वहां भोजन और वैक्सीन पहुंचाए। वहां के पर्यटन क्षेत्र को खड़ा करने के लिए मालदीव ने ऐसा योगदान दिया कि भारत के सरकारी खजाने में डॉलरों का ढेर लग गया। लेकिन अब वहां जो चीन समर्थक नई सरकार आई है, वह लगातार भारत को अपमानित करने का काम कर रही है। भारत ने पहले तो बेहद संयमित रुख अपनाया लेकिन जब मालदीव की तीन मंत्रियों ने भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणियां कर दीं और भारतीय पर्यटन क्षेत्र का नुकान उखाड़ा तो पूरे देश ने एक साथ खड़े होकर मालदीव को एक समक सिरसायि कि वह नजीर बन गया।

प्रधानमंत्री के खिलाफ मालदीव के तीन मंत्रियों ने मालदीव के गुराखा पर भारतीयों के राजदूत को बिदेस भेजवाने में तत्त्व कर भी अच्ची तरह से चुना दिया और हवाई टिकटों की बुकिंग रद्द होने लगी और सोशल मीडिया पर बॉयकोट मालदीव टूर होने लगा तो भारत सरकार घबरा गयी और आनन-फानन में उन तीन मंत्रियों को निलंबित कर दिया जिन्होंने भारतीय शासनी सरकार पर निशाना साह था। साथ ही मालदीव सरकार ने एक बयान जारी कर यह भी कहा कि मंत्रियों के बयान मालदीव की नीति के अनुरूप नहीं है। यही नहीं, मालदीव की पूर्व सरकार के मंत्रियों और पूर्व राष्ट्रपतियों ने भी अपने ही देश की सरकार के खिलाफ मोर्चा खड़ा किया और भरोसेमंद पड़ोसी भारत के खिलाफ की गयी टिप्पणियों को 'अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने' के समान बताया।

जो लोग 'नया भारत' क्या है, यह बात आज तक नहीं समझे हैं उन्हें जरा उन टिप्पणियों पर गौर करना लेना चाहिए जो रबौकाली मालीद्वर या इस्लाम देश के द्वीपों की संरक्षण जैसे हैरान के साथ लिखी गयी हैं। जिस तरह फिल्म उद्योग, खेल जगत और अन्य क्षेत्रों की हस्तियों ने प्रचामनीय के समर्थन में टिप्पणियां करते हुए मालदीव को खरी खरी सुनाई है उससे माले के पूर्व पर्यटन उद्योग को दिन में तारे दिख गये हैं। भारतीयों के रुख को देखते हुए अन्य देशों ने भी बड़ी प्रेरणा ले ली होगी क्योंकि आज के समय में भारतीय नागरिक ही कई देशों में पर्यटन अध्यवस्था में जान फूँक रहे हैं। इसके अलावा इस पूरे प्रकरण से लक्ष्यहीन के पर्यटन को बच बच लाना तय हो गया है क्योंकि अधिकतर लोगों ने वहां की यात्रा के खर्च जताई हैं। अपने वाले दिनों में संभव है कि वहां के लिए अर्थव्यवस्था से अधिक पलायन शुरू हो जाए ताकि लोग आसानी से वहां पहुंच सकें जहां तक मालदीव के मंत्रियों की टिप्पणियों पर भारत के अधिकारिक रुख की बात है तो भारतीय उद्योगों के स्तर पर तत्काल ही आपत्ति जता दी गयी थी लेकिन अब भारत में मालदीव के गुराखा को बिदेस भेजवाने में तत्त्व कर भी अच्ची तरह से चुना दिया गया है और मालदीव के कई मंत्रियों द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खिलाफ सोशल मीडिया पर पोस्ट की गई टिप्पणियों पर कट्टर धीमा व्यक्त की गई। हालांकि मालदीव सरकार अपने बयानों में तर्क दे रही है कि मंत्री के खिलाफ अपमानजनक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर रशियव को ही तीन उप मंत्रियों को निर्रिबित कर दिया गया है। हम आसानी बता दें कि तीनों उप मंत्रियों ने शहादती की यात्रा के बाद एक्स पर प्रधानमंत्री की ओर से की गयी पोस्ट के लिए उनकी आलोचना की थी और कहा था कि यह कट्टर नारायण प्रदेश को मालदीव के वैकल्पिक पर्यटन स्थल के रूप में पेश करने का एक प्रयास है।

प्रभु श्रीराम की किलकारियों को सुन आनंदित हुए अयोध्यावासी,

किये अयोध्या में होटल से लेकर किराया महंगा हो गया है। राम नगरी अयोध्या में देवी प्रसाद आदि

BASTI UTIAR PRADESH PIN
CODE-272301 Hareby solemnly
affirm and declare that I have
करार वाकई वाक़िफ किया गया हो
और जो कुल उमर अहम मुतल्लिका
प्रकाशक, मुद्रक प्रदीप चन्द्र
पाण्डेय द्वारा दर्पण प्रिन्टिंग

सर्व साधारण को सूचित किया जा रहा है कि मेरा माध्यमिक शिक्षा परिषद (J&MG) हाई स्कूल एवं 2018 अनुक्रमणक 2142428 एवं इंटर मीडिएट एवं 2020 अनुक्रमणक 2306867 को एक पत्र सह संक पत्र वास्तव में खो गया है।

(आकाश कुमार)
पुत्र भोला सोनकर
ग्राम व पोस्ट नगर बाजार
(माली टोला)
जनपद बस्ती।

आपको इतिला दी जाती है कि अगर बरोज मजदूर आप हाजिर न होंगे तो मुकदमा बर्गौर हाजिरी आपको मरममूर्त और फंसला होगा।

बखस मेरे दस्तखत और मुहर अदालत के आदारीखा मुह संत 20 ईं जारी किया गया।

द० हाकिम